भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3782**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्तुओं और सेवाओं संबंधी निर्यात

3782 श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, कॉफी और फार्मास्यूटिकल्स के निर्यात को बढ़ावा देने में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार ने निरंतर वृद्धि में सहयोग करने के लिए निर्यात और लॉजिस्टिक को सुदृढ़ करने हेतु कोई योजना प्रस्तावित की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत का कुल निर्यात – जिसमें पण्यवस्तु और सेवाएँ शामिल है – वर्ष 2024-25 में 824.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 6.02% की वृद्धि दर्शाता है। सेवा निर्यात प्रेरक शक्ति रहे, जिसने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13.6% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ रिकॉर्ड - तोड़ 387.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया। उल्लेखनीय रूप से, गैर-पेट्रोलियम व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात वर्ष 2024-25 में 374.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो अब तक का सबसे अधिक गैर-पेट्रोलियम वार्षिक निर्यात है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 6.0 प्रतिशत की बेहतर वृद्धि को दर्शाता है।

(ख) भारत ने पिछले दशक में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कॉफी और फार्मास्यूटिकल्स सहित प्रमुख क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने में उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे देश की समग्र निर्यात वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिला है और इसने भारत के निर्यात इकोसिस्टम तंत्र को सुदृढ़ किया है।

- प्रभावी नीतिगत उपायों के कारण **इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं** का निर्यात वर्ष 2014-15 के 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 38.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी अवधि के दौरान भारत के पण्यवस्तु निर्यात में उनकी हिस्सेदारी 2.02 प्रतिशत से बढ़कर 8.82 प्रतिशत हो गई।

इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 में 32.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

- **औषधियों और फार्मास्यूटिकल्स** के निर्यात में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो वर्ष 2014-15 में 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 30.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पण्यवस्तु निर्यात में उनकी हिस्सेदारी 4.97 प्रतिशत से बढ़कर 6.97 प्रतिशत हो गयी, जो इस क्षेत्र के लचीलेपन और वैश्विक मांग को दर्शाता है। दवाओं और फार्मा निर्यात में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 में 9.40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- **कॉफी** निर्यात दोगुने से अधिक हो गया है, जो वर्ष 2014-15 में 0.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इस वद्धि को अधिक मूल्यवर्धन और नए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार से सहयोग मिला है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वर्ष 2024-25 में कॉफी निर्यात में 40.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

(ग) और (घ) आर्थिक विकास को प्रेरित करने और वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अवसंरचना को सक्रिय रूप से सुदृढ़ कर रही है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जैसी प्रमुख पहलें कनेक्टिविटी बढ़ाने, लॉजिस्टिक्स को सुव्यवस्थित करने और निर्यात से संबंधित सुविधाओं के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करती हैं। लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने के लिए, एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज (एनएलडीएस) पारदर्शिता और उद्योग की सर्वोत्तम पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठा रही है। एनएलडीएस के मूल में लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक सिस्टम (एलडीबी) है, जो पूरे भारत में निर्यात-आयात कंटेनरों की रियल टाइम, सिंगल विंडो ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है – जो बेहतर निर्णय लेने और व्यापार संचालन को आसान बनाने में सहायता करता है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट (2023) के अनुसार, भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है, जो वर्ष 2018 में अपनी 44वीं रैंक और वर्ष 2014 में 54वें स्थान से सुधार करते हुए लॉजिस्टिक्स में इसकी बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रदर्शित करता है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, वाणिज्य विभाग वित्त वर्ष 2017-18 से निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (टीआईईएस) को कार्यान्वित कर रहा है। यह पहल निर्यात वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना के विकास और आधुनिकीकरण में केंद्रीय और राज्य सरकार के निकायों का समर्थन करती है। वर्ष 2025-26 के बजट में, सरकार ने 2,250 करोड़ रूपये के बजट आवंटन के साथ निर्यात संवर्धन मिशन की घोषणा की। इस मिशन की एक प्रमुख विशेषता भारत ट्रेड नेट का शुभारंभ है - एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसका उद्देश्य वैश्विक मानकों के अनुरूप व्यापार प्रलेखन और वित्तपोषण को सरल बनाना है।

*****